



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 19, 2007/कार्तिक 28, 1929

No. 349]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 19, 2007/KARTIKA 28, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2007

विषय :—मलेशिया, थाइलैंड, चीन और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित कैथोड रे रंगीन टेलिविजन पिकचर ट्यूबों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत ।

फा. सं. 14/8/2007-डीजीएडी.—मै. सेमटेल कलर लिमिटेड तथा जेसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने मलेशिया, थाइलैंड, चीन और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित तैयार अथवा अधूरी कैथोड रे रंगीन टेलिविजन पिकचर ट्यूबों के पाटन का आरोप लगाया है और पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करने तथा पाटनरोधी शुल्क प्रभारित करने का अनुरोध किया है ।

2. विचाराधीन उत्पाद

मौजूदा याचिका में विचाराधीन उत्पाद तैयार अथवा अधूरी कैथोड रे रंगीन टेलिविजन पिकचर ट्यूबें हैं जिन्हें अधिक विस्तृत रूप में “थर्मियोनिक” कोल्ड कैथोड अथवा फोटो कैथोड वाल्व्स और ट्यूबें जैसे कि वैक्यूम अथवा वेपर या गैस फिल्ड वाल्व्स और ट्यूबें, मर्करी आर्क रेक्टिफाइंग वाल्व्स और ट्यूबें कहा जाता है । इन्हें कैथोड रे ट्यूब, टेलिविजन कैमरा ट्यूब अथवा कैथोड रे रंगीन टेलिविजन पिकचर ट्यूब, या कलर टेलिविजन पिकचर ट्यूब, या कलर पिकचर ट्यूब आदि भी कहा जाता है और इस याचिका में कलर पिकचर ट्यूब या “सीपीटी” कहा गया है । तथापि वीडियो और कम्प्यूटर मॉनीटर रे ट्यूबों को मौजूदा याचिका के दायरे से बाहर रखा गया है । इन उत्पादों का प्रयोग मुख्यतः रंगीन टेलिविजन सेट में होता है । संबंधित वस्तुएँ सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के उपशीर्ष 8540.11 के तहत आती हैं सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से मौजूदा जाँच क्षेत्र को बाधित नहीं करता ।

3. घरेलू उद्योग की स्थिति

आवेदन मै. सेमटेल कलर लिमिटेड तथा जेसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा दर्ज किया गया है । याचिकाकर्ता ने मौजूदा जाँच से संबंधित सूचना दी है । संबंधित वस्तुओं का उत्पादन बीपीएल डिस्ले डिवाइसिज लिमिटेड और हॉटलाइन सीपीटी लिमिटेड द्वारा भी किया जाता है । याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है । याचिकाकर्ता कम्पनी का उत्पादन भारतीय उत्पादन

का प्रमुख हिस्सा है। जाँच के बाद प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता नियम 2(घ) के साथ पठित नियम 2(ख) के अर्थ के तहत घरेलू उद्योग है और आवेदन ऊपर उल्लिखित नियमावली के नियम 5 के अर्थ के भीतर संतोषजनक है।

4. शामिल देश

मलेशिया, थाइलैंड, चीन और कोरिया गणराज्य (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) से जाँचाधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के संबंध में याचिका दायर की गई है।

5. समान वस्तुएँ

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएँ संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित वस्तुओं के समान हैं। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा है कि तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से दोनों प्रतिस्थापन योग्य हैं। मौजूदा जाँच के लिए ऊपर उल्लिखित नियमावली के तहत याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

6. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के परिशिष्ट-1 के पैरा-7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि चीन के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अन्य संबद्ध देशों (जिन्हें बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश माना जा रहा है) के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

नियमावली के परिशिष्ट-1 के पैरा 7 के अनुसरण में चीन जन. गण. के संबंध में सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए थाइलैंड, कोरिया गणराज्य या मलेशिया को समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश चुने जाने की परिकल्पना की गई है। एतद्वारा हितबद्ध पक्षों से इस अधिसूचना में निर्धारित निश्चित समय सीमा के भीतर इस विकल्प के औचित्य पर टिप्पणी आमंत्रित की जाती है।

थाइलैंड, मलेशिया और कोरिया गणराज्य में सामान्य मूल्य को ध्यान में रखते हुए बिक्री, साधारण तथा प्रशासनिक अधिशीर्षों और यथोचित लाभ सहित उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर याचिकाकर्ता ने संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्यों का दावा किया है। सभी आकारों के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

7. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित अवधि में डीजीसीआई एंड एस, आईबीआईएस द्वारा प्रदत्त सौदे-वार आयात आंकड़ों तथा आईसीडी, दादरी से प्राप्त आयात संबंधी वास्तविक सूचना पर आधारित आयात

कीमत के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का दावा किया है। सभी आकारों के लिए अलग-अलग निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया है।

कारखाना-द्वार पर निर्यात कीमत की गणना के लिए निर्यातों के देश में समुद्र भाड़ा, समुद्र बीमा और अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन प्रहस्तन तथा पत्तन प्रभार पर समायोजनों का दावा किया गया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात कीमत के पर्याप्त प्रमाण हैं।

8. पाटन मार्जिन

कारखाना द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना सभी आकारों के लिए अलग से की गई है जो प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रत्येक देश से संबंधित काफी पाटन मार्जिन दर्शाता है। ऐसा समझा जाता है कि इस तथ्य के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या प्रमाण हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत से काफी अधिक है जो प्रथमतः इस बात का संकेत है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुएँ पाटित की जा रही हैं।

9. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ता ने घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति से संबंधित विभिन्न मानकों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है। निरपेक्ष रूप से आयातों में वृद्धि के साथ-साथ सापेक्ष रूप में भारत में उत्पादन तथा खपत, काफी कम कीमत पर बिक्री, मालसूचियों में वृद्धि, घरेलू उद्योग के बाजार अंश में वृद्धि, लेकिन जो माँग में वृद्धि के अनुपात में न हो, वित्तीय नुकसान में अत्यधिक वृद्धि, नकद लाभ तथा निवेश से होने वाली आय में अधिक कमी, प्रथमतः काफी कम कीमत पर बिक्री जैसे मानक सम्मिलित तथा संचित रूप से यह संकेत करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या प्रमाण हैं कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

10. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

और चूंकि प्राधिकारी को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या प्रमाण मिले हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा उक्त नियमावली के नियम 5 के तहत कथित पाटन और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की राशि बताई जा सके, जो यदि प्रभारित की जाए जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

11. जाँच की अवधि

मोजूदा जाँच के लिए जाँच अवधि 1 जुलाई, 2006 से 30 जून, 2007 (12 माह) है। हालांकि क्षति जांच की अवधि में 1 अप्रैल, 2004 से जाँच अवधि के अंत तक का समय शामिल होगा।

12. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों, उन देशों के दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबंधित आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे सभी संबद्ध सूचना निर्धारित रूप तथा तरीके से प्रस्तुत कर सकें। मौजूदा जाँच में हिस्सा लेने का इच्छुक कोई भी अन्य पक्ष इन्हें लिख सकता है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली - 110011

ऊपर उल्लिखित नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी जाँचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं तथा प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों, जो पाटन, क्षति तथा कारण संबंधी जाँच से संबद्ध सूचना प्रस्तुत कर सकें, को भी अवसर दे रहे हैं। कोई अन्य हितबद्ध पक्ष नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर जाँच से संबंधित आवेदन दे सकता है।

13. समय सीमा

क) सामान्य समय सीमाएँ

मौजूदा जाँच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित पते पर भेज दी जानी चाहिए। परिचित निर्यातक तथा आयातक, जिन्हें अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें लिखे गए पत्रों की तारीख से (40) चालीस दिन के भीतर सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा प्राप्त सूचना अधूरी पाई जाती है तो प्राधिकारी ऊपर उल्लिखित नियमावली के अनुसरण में रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

(ख) बाजार अर्थव्यवस्था देश के चयन के लिए विशेष समय सीमा

जाँच से जुड़े हितबद्ध पक्ष थाइलैंड, कोरिया गणराज्य तथा मलेशिया, जिन्हें इस जाँच शुरूआत अधिसूचना के पैरा 5 में चीन जन.गण. के संबंध में सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में परिकल्पित किया गया है, के औचित्य पर टिप्पणी कर सकते हैं। ये टिप्पणियाँ इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर भेज दी जानी चाहिए।

14. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार प्राधिकारी को प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना देने वाले किसी पक्ष के विचार में किसी सूचना का सार बनाना संभव नहीं है तो उन्हें इसके कारण से संबंधित विवरण प्रस्तुत करना होगा।

15. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखता है। कोई भी हितबद्ध पक्ष इस सार्वजनिक फाइल को देख सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों का अगोपनीय सार होता है।

16. असहयोग

यदि कोई हितबद्ध पक्ष सूचना देने से मना करता है या समुचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं करता अथवा जानबूझ कर जाँच में बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं और जैसा उचित समझें, केन्द्र सरकार से वैसी ही सिफारिश कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2007

Subject : Initiation of anti-dumping investigations concerning imports of Cathode Ray Colour Television Picture Tubes originating in or exported from Malaysia, Thailand, China and Korea RP.

F. No. 14/8/2007-DGAD.—M/s. Samtel Color Limited and JCT Electronics Limited has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of complete or incomplete cathode ray colour television picture tubes originating in or exported from Malaysia, Thailand, China and Korea RP and have requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

2. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration in the present petition is “complete or incomplete cathode ray colour television picture tubes”, more elaborately described as “thermionic, cold cathode or photo cathode valves and tubes such as vacuum or vapor or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, also called cathode ray tubes, television camera tubes or cathode ray colour television picture tubes, or colour television picture tubes, or colour picture tubes etc.” and has been referred to as Colour Picture Tubes or “CPT” in this petition. Video and computer monitor cathode ray tubes are however sought to be kept beyond the scope of the present petition. These products are mainly applied in colour television sets.

The subject goods fall under Chapter 85 of the Custom Tariff Act, 1975 under subheading no. 8540.11. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

3. DOMESTIC INDUSTRY STANDING

The application has been filed by M/s Samtel Color Limited and JCT Eleccronics Limited. The petitioner has provided information relevant to the present investigations. The subject goods are also produced by BPL Display Devises Limited and Hotline CPT

Limited. Production of the petitioner constitutes more than 50% of Indian production. Production of the petitioner company constitutes a major proportion in Indian production. The Authority after examination, has determined, that the petitioner constitutes domestic Industry within the meaning of the rule 2(b) read with 2(d) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

4. COUNTRIES INVOLVED

Petition has been filed seeking imposition of anti dumping duties on imports of the product under consideration from Malaysia, Thailand, China and Korea RP (hereinafter also referred to as subject countries).

5. LIKE GOODS

The petitioner has claimed that goods produced by domestic industry are like articles to the goods originating in or exported from subject countries. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the petitioner and those exported from subject countries. Petitioner claims that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of present investigation, the goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles to the product imported from the subject countries within the meaning of the Rules supra.

6. NORMAL VALUE

The petitioner has claimed that China PR should be treated as non-market economy and have determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the anti dumping rules. The petitioner has submitted that normal value determined for other subject countries (which are being treated market economy countries) may be considered for determination of normal value for China.

In accordance with Para 7 to Annexure-I of the Rules, it is envisaged to choose Thailand, Korea RP or Malaysia as an appropriate market economy country for the purpose of establishing normal value in respect of China PR. Interested parties are hereby invited to comment on the appropriateness of this choice within the specific time limit laid down in this notification.

With regard to normal value in Thailand, Malaysia and Korea RP, petitioner has claimed normal values for the subject goods considering estimates of cost of production including selling, general & administrative overheads and reasonable profit. Normal value has been separately determined for all sizes.

7. EXPORT PRICE

Petitioner has claimed export price of the subject goods from the subject countries on the basis of import price in the proposed period, based on transaction wise import data

provided by the DGCI&S, IBIS and actual information on imports reported at ICD, Dadri. Export price has been separately determined for all sizes.

Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance and inland transportation in the country of exports, port handling and port charges to arrive at ex-factory export price. There is sufficient evidence of the export price for the subject goods from the subject countries.

8. DUMPING MARGIN

Normal value and export price have been compared at ex-factory level, separately for all sizes, which shows significant dumping margin in respect of each of the subject countries for each of the product. It is considered that there is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries.

9. INJURY AND CAUSAL LINK

Petitioner has furnished information on various parameters relating to material injury to the domestic industry. Parameters such as increase in imports in absolute terms as also relative to production and consumption in India, significant price underselling, increase in inventories, Increase in the market share of the domestic industry but not in proportion to increase in demand, significant increase in financial losses , significant decline in cash profit and return on investment, significant price underselling, prima facie, collectively and cumulatively indicate that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping of subject goods from subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the domestic industry has suffered material injury as a result of dumped imports.

10. INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the said Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

11. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st July, 2006 to 30th June, 2007 (12 months). However, the period for injury examination would cover periods from 1st April 2004 to the end of the POI.

12. SUBMISSION OF INFORMATION

The exporters in the subject countries and their Government through their embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

13. TIME LIMIT

a) **General Time Limits**

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within (40) forty days from the date of the letter addressed to them. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

b) **Specific time limit for selection of market economy country**

Interested parties to the investigation may wish to comment on the appropriateness of Thailand, Korea RP and Malaysia which, as mentioned in the Para 5 of this initiation notification, envisaged as a market economy country for the purpose of establishing normal value in respect of the China PR. These comments must be submitted within two weeks from the date of publication of this notification.

14. SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

In terms of Rule 7, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion

of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided.

15. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6(7), Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

16. NON COOPERATION

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

E. GOPALAN, Designated Authority

466862/07-2